कानपुर, बुधवार, 28 जनवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 29, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड पुलिस पहरे में अलंकार अग्निहोत्री...>Pg12

मरीज को दो दिन बाद मिल सकी दवा...>Pg03

मूल्यः 2 ₹

चार्टर्ड विमान क्रैश, उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 की जिंदगी खत्म

लैंडिंग के दौरान हादसा, विमान में लगी आग, डीजीसीए/एएआईबी ने शुरु की जांच

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

बारामती/मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार को ले जा रहा प्राइवेट चार्टर्ड विमान बुधवार सुबह बारामती हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी पाँच लोगों की मौत हो गई। घटना की आधिकारिक पुष्टि के बाद राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है।

जानकारी के अनुसार, विमान लैंडिंग के समय संतुलन खो बैठा और रनवे के पास गिरकर आग की चपेट में आ गया, जिससे वह पूरी तरह जल गया। दुर्घटना के कारणों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। तकनीकी खराबी या दृश्यता कम होने जैसे पहलुओं की जांच की जा रही है। सूचना मिलते ही प्रशासन, दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचे, लेकिन आग की तीव्रता के कारण किसी को बचाया नहीं जा सका।

बताया गया है कि अजित पवार बारामती में जिला परिषद चुनाव से जुड़ी रैली/कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। विमान में उपमुख्यमंत्री के अलावा एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक सहायक/स्टाफ सदस्य और दो क्रू मेंबर (पायलट सहित) सवार थे। विमान कंपनी का दावा है कि उड़ान से पहले किसी तकनीकी खराबी की सूचना नहीं थी, हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। उधर, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। फ्लाइट डेटा, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मौसम और एटीसी संचार की पड़ताल की जा रही है।

अजित पवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि

अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। वे छह बार उपमुख्यमंत्री रह चुके थे और 'अजित दादा' के नाम से लोकप्रिय थे। प्रशासनिक पकड़ और जमीनी राजनीति के लिए उनकी पहचान रही। उनके आकस्मिक निधन से राज्य की राजनीति में बड़ा शून्य पैदा होने की बात कही जा रही है। अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राष्ट्रीय नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। शोक संदेशों में उन्हें जननेता और कुशल प्रशासक बताया गया है।

देश में हुई विमान व हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इन हस्तियों की गई जान

1. अजित पवार 28 जनवरी 2026 में विमान दुर्घटना में निधन
2. विजय रुपाणी 12 जून 2025 के विमान हादसे में मृत्यु
3. दॉर्ज़ी खांडू 30 अप्रैल 2011 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना
4. माधवराव सिंधिया 30 सितंबर 2001 में विमान क्रैश
5. संजय गांधी 23 जून 1980 में विमान दुर्घटना
6. जी.एम.सी. बलयोजी 3 मार्च 2002 में हेलीकॉप्टर क्रैश
7. ओ.पी. जिन्दल (राज्य मंत्री) 31 मार्च 2005 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना
8. डेरा नादुंग मई 2001 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना
9. गुरनाम सिंह 1973 में विमान दुर्घटना (पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब)
10. बालवनत्राई मेहता 1965 में विमान दुर्घटना में मृत्यु

- बारामती में लैंडिंग के दौरान चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पाँच लोगों की मौत
- रनवे के पास गिरते ही विमान में लगी आग
- डीजीसीए/एएआईबी ने जांच शुरू की
- तकनीकी खराबी या कम दृश्यता की जांच जारी
- देश-भर में शोक, नेताओं की संवेदनाएँ

माघ मेला बीच में छोड़ कर लौटे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

मौनी अमावस्या विवाद के बाद 11 दिन धरने पर रहे, बिना संगम स्नान किए काशी रवाना

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

प्रयागराज। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला बीच में ही छोड़ दिया। बुधवार सुबह वह प्रयागराज से काशी के लिए रवाना हो गए। यह पहला अवसर है जब माघ मेले में पहुंचने के बावजूद शंकराचार्य बिना संगम स्नान किए लौटे हैं।

मौनी अमावस्या के दिन पुलिस-प्रशासन से हुए विवाद के बाद शंकराचार्य ने न तो संगम स्नान किया और न ही अपने शिविर में प्रवेश किया। विवाद के बाद वह लगातार शिविर के बाहर धरने पर बैठे रहे। मंगलवार देर रात समर्थकों से विचार-विमर्श के बाद माघ मेला छोड़ने का निर्णय लिया गया।

हालांकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शंकराचार्य माघ पूर्णिमा तक प्रयागराज में ही रहेंगे, लेकिन उनके अचानक प्रस्थान से संत समाज और श्रद्धालुओं में हलचल मच गई है। माघ मेला छोड़ने से पहले शंकराचार्य ने कहा कि वह अन्याय के विरोध में प्रयाग आए थे और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रयाग की धरती आध्यात्मिक शांति का केंद्र है, लेकिन यहां से उन्हें अत्यंत पीड़ा और भारी मन के साथ

लौटना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि संतों के साथ हुए अन्याय पर प्रशासन ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई।

शंकराचार्य पहले यह भी कह चुके थे कि वह माघ मास मेला समाप्त होने तक प्रयाग नहीं छोड़ेंगे और यदि वह गए तो तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी। उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि संतों के साथ हुई घटना किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है और इसके पीछे हुक्मरानों का इशारा है। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर आशंका जताई थी। इन तमाम आरोपों, आशंकाओं और प्रशासनिक उपेक्षा के बीच शंकराचार्य का माघ मेला बीच में छोड़कर लौटना अब प्रशासन और सरकार के सामने कई नए सवाल खड़े कर रहा है।

- मौनी अमावस्या पर पुलिस-प्रशासन से विवाद के बाद संगम स्नान नहीं किया
- 11 दिन तक शिविर के बाहर धरने पर बैठे रहे शंकराचार्य
- माघ पूर्णिमा तक रुकने की चर्चा थी, लेकिन अचानक काशी रवाना
- संतों के साथ अन्याय और प्रशासनिक असंवेदनशीलता का आरोप
- सुरक्षा को लेकर पहले भी जता चुके हैं गंभीर आशंका

एडीएम सिटी कोर्ट ने 95 मिलावटखोरों पर 31.20 लाख ठोका जुर्माना

अर्सिया फूड का पनीर,बर्गर किंग का रिफाइंड मिला घटिया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर.। खाद्य पदार्थों में मिलावट कर जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर एडीएम सिटी की कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। नमूने फेल आने पर दिसम्बर 2025 में 95 मिलावटखोरों की सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने 31.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बर्गर किंग का रिफाइंड और अर्सिया फूड का पनीर घटिया मिला है।

एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि मिलावटखोरों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थ सीधे आम लोगों की सेहत से जुड़े हैं। ऐसे में मिलावट या घटिया गुणवत्ता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कुछ बडे मामले

जेड स्क्वायर में राहुल कटियार की बर्गर किंग प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया रिफाइंड पॉमोलिन तेल जांच में पूरी तरह से घटिया पाया गया। 75 हजार रुपये का जुर्माना

लगाया गया। जेड स्क्वायर स्थित अर्सिया फूड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के पनीर के नमूने में फैट की मात्रा 50 प्रतिशत से कम पाई गई। इसे सब स्टैंडर्ड मानते हुए कोर्ट ने 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।

राजधानी पान मसाला का नमूना फेल पाए जाने पर एक लाख रुपये, गगन ब्रांड पान मसाला के सैंपल फेल होने पर ग्रीन वर्थ इंटरप्राइजेज पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।इसके अलावा मेसर्स नितिश टी कंपनी की खुली चायपत्ती का नमूना भी मानकों पर खरा नहीं उतरा। 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

बोतल बंद पानी की जांच में 8 की क्वालिटी गड़बड़, 4 के लाइसेंस सस्पेंड

कानपुर में बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियां खराब पानी बेच रही हैं। यह जानकारी जांच के बाद सामने आई है। आठ ऐसी कंपनी मिली है, जिसका बोतल बंद पानी खराब क्वालिटी का है। उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है।

शहर और आसपास संचालित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के प्रोसेस यूनिटों के विरुद्ध सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कुल 26 यूनिटों का निरीक्षण किया। इसमें 10 यूनिटें बंद पाई गईं। निरीक्षण में जो 16 कंपनियां चलती मिली हैं, उनमें से आठ के पानी की क्वालिटी गड़बड़ मिली।डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आगे भी अभियान संचालित किए जाएंगे।निरीक्षण में कई इकाइयों में निर्धारित मानकों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। जिला प्रशासन की ओर से चार यूनिट्स के लाइसेंस सस्पेंड करने की संस्तुति करते हुए केंद्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। वहीं चार स्टेट लाइसेंस प्राप्त यूनिटों की खाद्य अनुज्ञप्ति को सस्पेंड कर दी गई।

इनके लाइसेंस किए गए सस्पेंड

सस्पेंड की गई स्टेट फूड लाइसेंस से संबंधित फर्मों में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मेसर्स प्रभु कृपा एंटरप्राइजेज, यशोदा नगर स्थित केएस टेस्टी ड्रिंक्स एंड रिफ्रेशमेंट सॉल्यूशन, गोविंद नगर स्थित संतोषा इंडस्ट्रीज व हंसपुरम नौबस्ता स्थित सत्यम एंटरप्राइजेज शामिल हैं।

इन यूनिटों के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति

इसी प्रकार जिन केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त यूनिटों के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई है, उनमें उद्योगकुंज पनकी स्थित मेसर्स डैडीज एंटरप्राइजेज, इस्पात नगर पनकी स्थित मेसर्स प्रयाग पैकर्स, रूमा स्थित मेसर्स विवान एंटरप्राइजेज तथा सचेंडी स्थित मेसर्स एचडी ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस शामिल हैं।

रेस्टोरेंट की लिफ्ट में आधे घंटे फंसे रहे मां-बेटा, रेस्क्यू कर निकाले गए

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। काकादेव थाना क्षेत्र के शिवाजीनगर में स्थित हल्दीराम रेस्टोरेंट में मंगलवार रात कॉफी पीकर लौटते समय फॉल्ट होने के कारण लिफ्ट बंद होने से मां-बेटा आधे घंटे फंस गए। सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने टेक्नीशियन की मदद से 15 मिनट में रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाल लिया।

रामकृष्णनगर निवासी रजनीश गुप्ता अपनी मां कस्तूरी गुप्ता का चेकअप कराने के लिए लाजपतनगर स्थित एक निजी हॉस्पिटल मंगलवार रात करीब नौ बजे गए थे। डॉक्टर को दिखाने के बाद वह दोनों शिवाजीनगर स्थित रेस्टोरेंट में प्रथम तल पर कॉफी पीने गए। घर लौटने के लिए मां बेटा लिफ्ट में घुसे। वह लोग नीचे उतर ही रहे थे, कि अचानक लिफ्ट बंद हो गई और अंधेरा छा गया।

शोर मचाने पर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ लग गई। रेस्टोरेंट कर्मियों ने मदद के लिए दमकल विभाग को सूचना दी।मौके पर कुछ ही देर में मुख्य अग्शिमन अधिकारी दीपक शर्मा, फायर स्टेशन अफसर परमानंद पांडेय समेत दमकल की टीम पहुंची ।

22 आलाधिकारियों ने अब तक नहीं भेजा नोटिस का जवाब

» एडीएम सिटी बोले-भेजेंगे नोटिस का रिमाइंडर

» 73वीं आईजीआरएस रैंक पर भी गंभीर नहीं अफसर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। 75 जिलों में आईजीआरएस की 73वीं रैंक आने के बाद भी विभागीय अफसरों में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा है। रैंक गिरने को लेकर बीते रोज 22 आलाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब तक इसपर कोई भी जवाब नहीं आया है। आलम यह है कि आईजीआरएस की आने वाली शिकायतों के निस्तारण को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन कुछ विभागों की ढिठाई कारगुजारी से सब मामला टांय टांय फिस्स हो जा रहा है। एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि 22 विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, अब तक जवाब नहीं आए हैं। इस संबंध में रिमाइंडर जारी किया जाएगा।

आईजीआरएस की लगातार गिरती रैंक के जिम्मेदार 22 आलाधिकारियों को डीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें पूछा

गया है कि आखिर निगेटिव फीडबैक को लेकर अफसर क्या कार्यवाही कर रहे हैं और संबंधित पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

दिसम्बर में आईजीआरएस रैंक में फिर से गिरावट आने के बाद अब प्रशासन काफी तल्ख कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। आईजीआरएस के प्रकरणों में रुचि न लेने, अधिकांश मामलों में शिकायतकर्ताओं से संपर्क न करने, निगेटिव फीडबैक के चलते इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इनको भेजा नोटिस

- 1. अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)-
- 2. बेसिक शिक्षा अधिकारी
- 3. खण्ड विकास अधिकारी कल्यानपुर-
- 4. विकास प्राधिकरण
- 5. जिला विद्यालय निरीक्षक
- 6. मुख्य चिकित्साधिकारी
- 7. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम
- 8. प्रभागीय वन अधिकारी
- 9. उपनिदेशक कृषि विभाग
- 10. नगर निगम
- 11. सहायक श्रमायुक्त
- 12.अधिशासीअभियन्तादक्षिणांचल
- वि0वि0नि0लि0
- 13. जिला प्रोबेशन अधिकारी
- 14. केस्को,
- 15. जिला कार्यक्रम अधिकारी
- 16. सामान्य प्रबन्धक उद्योग
- 17. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी-
- 18. उ0प्र0 जल निगम नगरीय
- 19. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता
- 20. मुख्य चिकित्साधिकारी पशुपालन
- 21. उपजिलाधिकारी सदर
- 22. उपजिलाधिकारी बिल्हौर

ईएसआईसी बीमित मरीज को दो दिन बाद मिल सकी दवा

बहाने बाजी की हद, डॉक्टर चले जाते नाश्ता करने, फार्मासिस्ट को आने लगते दस्त

10 बजे तक नहीं खुलता अस्पताल, बायोमेट्रिक अटेंडेंस में भी चल रहा खेल

02 दिन दौड़ने के बाद मेडिकल इंचार्ज ने देखी अनियमितता, मरीज को दिलाई दवा

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर का जाजमऊ स्थित बीमा अस्पताल यूँ तो बड़ा अस्पताल है , बीमित कर्मचारियों के लिए ढेरों सरकारी सुविधाओं की योजनाएं यहाँ लागू हैं लेकिन बीमित कर्मचारियों के हित की योजनाएं यहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही और घोर अनियमित्ता की भेंट चढ़ गईं। मनमर्जी से अस्पताल चलाया जा रहा है। बायोमेट्रिक हज़ारी कैसे मैनेज हो रही यह जांच का विषय है। बुधवार को बीमित कर्मचारी तो जाजमऊ अस्पताल समय से पहुंचे लेकिन डाक्टर और कर्मचारी समय से नहीं पहुंचे। एक बीमित कर्मचारी ने बताया उसने मंगलवार को कमरा न0 4 में डॉ0 रवि शुक्ला को दिखाया था। जो कि अपने निर्धारित समय 9 बजे के बाद 9:30 पर आये उन्होंने दवा लिखी लेकिन दवा का पर्चा चढाने वाली कार्यरत मैडम नास्ता करने गई थी। मैडम के न होने से बीमित कर्मचारी फैक्टरी लौटने का हवाला देकर चला गया। ओपीडी में 9:40 बजे तक भी कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं मिला। दवा काउंटर 10 बजे तक बंद था । बताया गया कि दवा बाँटने वाले टट्टी करने गए हैं। इसकी शिकायत जब बीमित कर्मचारी ने सीएमओ जाजमऊ अस्पताल डॉ0 आकाश जायसवाल से की तो उन्होंने बताया वह दो दिन के अवकाश पर है उन्होंने कमरा न0 11 डॉक्टर रामकुमार से मिलने को बोला जब उनको शिकायत की गई तो डॉ0 फवाद ने मौके जाकर मुआयना किया। इसी क्रम में पाया कि स्टाफ ऋषभ मिश्रा और प्रदीप चौहान गैर हाजिर है। उन्होंने अपने साथ अन्य कर्मचारी से बीमित कर्मचारियों को दवा वितरित कराई और मामले को संज्ञान लेने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

इस संबंध में सीएमओ ईएसआई डॉक्टर आकाश जायसवाल से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया.

यूजीसी कानून के विरोध में क्षत्रिय समाज का ज्ञापन, 7 फरवरी से अनशन की चेतावनी

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर । यूजीसी के नवीन कानून के विरोध में क्षत्रिय समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी कानपुर नगर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रस्तावित यूजीसी कानून स्वर्ण समाज के बच्चों के हित में नहीं है और भविष्य में इसके दुरुपयोग की प्रबल आशंका है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि यह कानून शिक्षा से वंचित करने, मानसिक प्रताड़ना देने और निर्दोष युवाओं को अपराधी घोषित करने का माध्यम बन सकता है। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि केवल स्वर्ण परिवार में जन्म लेना ही अपराध की तरह देखा जा रहा है और सरकार की नीतियों से एक वर्ग को प्रताड़ित जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

प्रार्थियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे इस कानून को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि

यदि आगामी 7 फरवरी तक यह कानून वापस नहीं लिया गया तो क्षत्रिय समाज सामूहिक रूप से अनशन पर बैठने को बाध्य होगा।

ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया कि इस विषय को प्रधानमंत्री के संज्ञान में तत्काल लाया जाए और यूजीसी के इस कानून को प्रभावी रूप से वापस लिया जाए।

थाने से फरार चोर मुठभेड़ में पुलिस की गोली से हुआ लंगड़ा

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। गुजैनी थाना पुलिस ने होमगार्ड को धक्का देकर थाने से फरार हुए आरोपी विशाल उर्फ कल्लू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे मौके से दबोचकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

आरोपी को जरौली फेस-टू स्थित बालाजी ज्वैलर्स से तीन किलो चांदी के जेवर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 15 जनवरी को जेल भेजे जाने से पहले आरोपी ने बाथरूम जाने का बहाना बनाकर हवालात से बाहर निकलते हुए ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को धक्का दिया और फरार हो गया था।जानकारी के अनुसार, गुजैनी थानाक्षेत्र के गोपालपुरम सोसाइटी निवासी गौरव वर्मा की बालाजी ज्वैलर्स दुकान में 14 दिसंबर 2024 की देर रात तीन नकाबपोश चोरों ने शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। महज 36 मिनट में चोर तीन किलो चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 20 दिसंबर को मामले का खुलासा करते हुए गुजैनी गांव निवासी विशाल गुप्ता उर्फ मन्नू बिहारी और मायापुरम कच्ची बस्ती निवासी करन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि विशाल उर्फ कल्लू फरार चल रहा था।गुजैनी पुलिस ने 14 जनवरी की रात उसे दोबारा किसी वारदात की फिराक में घूमते हुए गिरफ्तार किया था। अगले ही दिन वह पुलिस कस्टडी से फरार हो गया।

डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मंगलवार देर रात बनपुरवा इलाके

⇨ होमगार्ड को धक्का देकर पुलिस कस्टडी से भागा था आरोपी, ज्वैलरी शॉप में चोरी का है आरोप

में आरोपी के देखे जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असलहा भी बरामद किया है।

उथल-पुथल

केडीए का बड़ा एक्शन जारी

14 बीघा क्षेत्र में अवैध निर्माण व प्लॉटिंग पर बुलडोजर, सीलिंग व नोटिस की कार्रवाई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध निर्माण एवं अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को प्रवर्तन जोन-1बी के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की। उपाध्यक्ष श्री मदन सिंह गुर्ब्याल के निर्देशन में लगभग 14 बीघा क्षेत्रफल में फैले अवैध विकास कार्यों पर ध्वस्तीकरण, सीलिंग एवं नोटिस की कार्यवाही की गई।

विशेष कार्याधिकारी/उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में जागेश्वर मंदिर के सामने परमियापुरवा, मैनावती मार्ग स्थित लगभग 08 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को तीन जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान रोड, नाला, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर, एंट्री गेट सहित समस्त अवैध संरचनाएं समाप्त की गईं। यह प्लॉटिंग बिना केडीए से स्वीकृत मानचित्र व अनुमति के की जा रही थी।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28(क) के अंतर्गत बैकुण्ठपुर, मंधना क्षेत्र में लगभग 03 बीघा में किए गए अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। यह निर्माण भी बिना स्वीकृत नक्शे के किया गया था।

केडीए की संयुक्त प्रवर्तन टीम ने मौके पर ही दो अन्य अवैध निर्माण/विकास कार्यों को चिन्हित करते हुए संबंधित विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किया। इनमें बैकुण्ठपुर क्षेत्र में बिना मानचित्र के हो रहे निर्माण एवं प्लॉटिंग शामिल हैं।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि कल्यानपुर व बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 07 बीघा क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग पहले ही चिन्हित की जा चुकी है, जिन पर शीघ्र ही कार्रवाई प्रस्तावित है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

इस कार्रवाई में क्षेत्रीय अभियंता, सुपरवाइजर, कर्मचारीगण एवं थाना बिठूर का पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा।

केडीए की इस सख्त पहल से अवैध कॉलोनाइज़रों में हड़कंप मच गया है और आम नागरिकों ने प्राधिकरण की कार्रवाई का स्वागत किया है।

निजीकरण का टेंडर निरस्त नहीं होगा, आंदोलन खत्म

संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले मोती झील में विशाल आम सभा आयोजित हुई

» नगर निगम अफसरों के रवैय्या से कर्मचारियों में बढ़ रही नाराज़गी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर ।संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के तत्वावधान में सोमवार को दोपहर 1ः00 बजे मोती झील स्थित मुख्यालय परिसर में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 26 जनवरी को संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मंडला आयुक्त, कानपुर मंडल से मिला था। इस दौरान मंडला आयुक्त ने नगर आयुक्त को दूरभाष पर निर्देशित किया कि कर्मचारियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके क्रम में नगर आयुक्त द्वारा शाम 4ः00 बजे प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया।

वार्ता के दौरान नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग एवं रविस विभाग के निजीकरण से संबंधित टेंडर निरस्त नहीं किए जाएंगे। हालांकि, कर्मचारियों को ईपीएफ एवं ईएसआई का लाभ प्रदान किया जाएगा। सेवा निगम बोर्ड द्वारा शासनादेश के अनुरूप जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसे प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त फेस अटेंडेंट मशीन में तकनीकी खराबी दूर होने तक पूर्व की भांति वेतन भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया गया। संविदा सफाई कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य पर रखने का निर्णय भी लिया गया। कर्मचारियों की 5ः00 बजे की ड्यूटी के संबंध में शासनादेश के अनुसार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छूट देने पर सहमति बनी।

सभा में प्रमुख रूप से किशनलाल सुदर्शन, रमाकांत मिश्र, धीरज गुप्ता, हरिओम वाल्मीकि, अजीत बाघमार, उस्मान अली शाह, जयपाल सिंह, कमरुद्दीन, विनोद कुमार रावत, पिंटू चौधरी, मुन्ना हजारिया, सी.एल. बड़ेल, नीलू निगम, रामगोपाल चौधरी, मुन्ना पहलवान, नरेंद्र खन्ना सहित अनेक पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सभा को संबोधित करते हुए संयोजक मंडल के सदस्य अजीत बाघमार ने कहा कि संघर्ष समिति कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

निराशा में कर्मचारी, हताशा में नेता

नगर निगम कानपुर में कई दिनों से चल रहे आंदोलन में कर्मचारियों के हाथ सिर्फ निराशा लगी है .कर्मचारी नेताओं के तमाम प्रयासों के बाद भी निजीकरण का टेंडर निरस्त नहीं किया गया, वहीं अन्य मांगे पूरी होगी कि नहीं इस पर भी कोई ठोस आश्वासन नहीं है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारियों की मांगों का कैसे निराकरण होगा.

सम्पादकीय

मासूमों को मिले स्नेह व हौसले का संबल

पिछले दिनों फरीदाबाद में ठीक से पढ़ाई न कर सकने वाली बच्ची की पिता द्वारा पिटाई करने से हुई मौत की खबर ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोरा है। यह विश्वास करना कठिन है, कोई पिता इतना क्रूर हो सकता है कि महज गिनती न सीख पाने के कारण बच्ची की जान ले ले। यदि इस घटना के पीछे कोई परोक्ष कारण नहीं है तो निश्चय ही यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिये कलंक ही कही जाएगी। यह शर्म की बात ही है कि इस ज्ञान की सदी में किसी बच्ची की पिता के हाथों पढ़ाई के नाम पर मौत हो जाए। यह विडंबना ही है कि 21वीं सदी में भी हमारे समाज में मानसिक ग्रंथि की वह गांठ नहीं खुल पाई है, जो मानती है कि डर व मारपीट से बच्चों को सिखाया जा सकता है। ऐसी तमाम घटनाएं आज भी हमारे स्कूलों व घरों तक में सामने आती हैं। यदि स्कूल या कोचिंग में किसी बच्चे-बच्ची के साथ पढ़ाई के नाम पर आक्रामक व्यवहार होता है तो उम्मीद की जाती है कि परिवार उसके साथ मुश्किल समय में खड़ा होगा। लेकिन जब घर में माता-पिता ही हिंसक व्यवहार करने लगें तो मासूम किसके भरोसे रहेगा... कहने को देश में बच्चों के साथ होने वाले किसी भी हिंसक व्यवहार को रोकने के लिये तमाम तरह के प्रावधान सुरक्षा कवच उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जब प्रवर्तन एजेंसियां ही उदासीन रहेंगी तो समस्या का समाधान संभव ही नहीं है। पहले तो स्कूलों में ही ऐसे मामलों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, फिर यदि मामला पुलिस या संबंधित विभाग के संज्ञान में आता भी है तो उसे रफा-दफा करने के प्रयास तेज हो जाते हैं। ऐसे मामलों में शिक्षक अभिभावक संगठन की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। जिसमें अकसर शिक्षण संस्था के सुर में बोलने वाले अभिभावकों को ही रखा जाता है। आज भी यह एक गंभीर समस्या है और इसके गंभीर समाधान की जरूरत महसूस की जा रही है।

यह हमारे समाज की विडंबना ही कही जाएगी कि आज भी यह सोच बलवती है कि बच्चों के साथ सख्त व्यवहार से उनकी पढ़ने-लिखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जबकि हकीकत यह है कि किसी भी आक्रामक व्यवहार से बच्चों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देश व दुनिया में हुए तमाम शोध व अध्ययन बताते हैं कि बच्चों के साथ सख्त व आक्रामक व्यवहार किए जाने से बच्चों की एकाग्रता व याद?दाश्त पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। जिसका नकारात्मक असर यह होता है कि बच्चे हीनभावना से ग्रसित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी कक्षा में पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। कालांतर यह भय व कुंठा जीवनभर उनका पीछा करती है। उनका आत्मविश्वास डिग जाता है। तब वे जीवन की स्पर्धा में भी दब्बू बनकर रह जाते हैं। यह भी विडंबना ही है कि आज भी बच्चों पर पढ़ाई का बोझ थोपने से पहले हमारे यहां किसी तरह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं होता है कि बच्चे की अभिरुचि किन विषयों में है। सही मायनों में हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। कुदरत उसकी रचना किसी खास मकसद के लिये करती है। यदि समय रहते बच्चे की उस प्रतिभा को पहचाना जा सके और उस विषय व दिशा में उसे प्रोत्साहित किया जाए, तो वे अप्रत्याशित रूप से किसी भी क्षेत्र में शिखर की सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे कई तरह के जन्मजात व आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, जो उनकी सामान्य पढ़ाई में बाधक हो सकता है। कई बच्चों में जन्म से ही दृष्टि दोष या कोई अन्य शारीरिक व मानसिक विकार भी हो सकता है, जिसके चलते वे अपनी पढ़ाई को ठीक से पूरा नहीं कर पाते। फलतः उन्हें शिक्षकों व परिजनों के हिंसक व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। आज बच्चों को संवेदनशील ढंग से देखने की जरूरत है ताकि उनकी पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर किया जा सकेयदि स्कूल या कोचिंग में किसी बच्चे-बच्ची के साथ पढ़ाई के नाम पर आक्रामक व्यवहार होता है तो उम्मीद की जाती है कि परिवार उसके साथ मुश्किल समय में खड़ा होगा।

एफटीए से यूरोप-भारत व्यापार को बूस्टर डोज़

यशवंत सचदेव

अब देखना होगा कि यह बहु-प्रतीक्षित समझौता भारत के 140 करोड़ और यूरोपीय संघ के 45 करोड़ लोगों हेतु कितना बड़ा अवसर लाता है। इंतज़ार रहेगा कि एफटीए का ईयू-अमेरिका व भारत-चीन के उभयपक्षीय संबंधों पर क्या असर पड़ता है।... अब देखना होगा कि यह बहु-प्रतीक्षित समझौता भारत के 140 करोड़ और यूरोपीय संघ के 45 करोड़ लोगों हेतु कितना बड़ा अवसर लाता है। इंतज़ार रहेगा कि एफटीए का ईयू-अमेरिका व भारत-चीन के उभयपक्षीय संबंधों पर क्या असर पड़ता है।बिना एफटीए के भी यूं तो यूरोपीय देशों से भारत का व्यापार दशकों से होता आ रहा है। लेकिन, ऐसा माना गया कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होने से इसे बूस्टर डोज़ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए कहा, 'ईयू-इंडिया एफटीए सभी सौदों की जननी है। यह सौदा यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों का पूरक है। भारत में कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा और जूट जैसे विभिन्न क्षेत्रों को इस व्यापार समझौते से फायदा होने वाला है।' पीएम मोदी ने कहा कि यह डील भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करेगी, और सर्विस सेक्टर को नया सहारा देगी।

वर्ष 2007 में शुरू हुई वार्ता प्रक्रिया का समापन देर-सवेर हुआ ही। मनमोहन सिंह से आरम्भ वार्ता को मोदी ने अंजाम दिया। यहां तक पहुंचने में 19 साल लगे। लेकिन रुकिए, अभी बहुत कुछ होना बाक़ी है। सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की भाषाओं में एफटीए के कानूनी दस्तावेज़ों को प्रकाशित करना होगा। सभी धाराओं की एक-एक करके जांच होगी, जिसे 'लीगल स्क्रबिंग' कहते हैं, यूरोपीय परिषद द्वारा औपचारिक मंजूरी के बाद, यूरोपीय संसद की सहमति चाहिए, इसके प्रकारांतर भारतीय कैबिनेट द्वारा पुष्टि होगी। इन सबसे गुज़रने के बाद, 2027 तक इसके लागू होने की उम्मीद है। मंगलवार को यूरोपियन कमीशन की प्रतिक्रिया ग़ौर करने लायक है– 'इस डील से ईयू कंपनियों और किसानों को ज़्यादा निर्यात करने में मदद मिलेगी। इस डील से पहले ही आठ लाख यूरोपीय नौकरियों को सपोर्ट मिलता रहा है। अब एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से, और भी ज़्यादा यूरोपीय नौकरियां मिल सकती हैं।' यूरोपियन कमीशन का सन्देश था, 'उम्मीद है कि यह समझौता भारत को होने वाले ईयू एक्सपोर्ट को दोगुना कर देगा। इसके अलावा, भारतीय सर्विस मार्केट तक बेहतर पहुंच, खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज़, मैरीटाइम सर्विसेज़ और दूसरे मुख्य सेक्टर्स में, नए बिज़नेस और रोज़गार के अवसर पैदा करेगी।' यूरोपीय आयोग ने जानकारी दी, कि इस डील से 90 फीसद से ज़्यादा यूरोपीय संघ के देशों के सामानों के एक्सपोर्ट टैरिफ खत्म, या कम कर दिया जाएगा। इससे यूरोपीय प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी में हर साल अरबों यूरो तक की बचत होगी। यूरोपियन कमीशन ने कहा, 'भारत ने किसी भी व्यापारिक सहकार को इतनी बड़ी ट्रेड ओपनिंग नहीं दी है। इससे एक्सपोर्ट को तेज़ और आसान बनाने के लिए कस्टम प्रक्रियाओं को सहज बनाया जायेगा।' 27 जनवरी को डील के तुरंत बाद यूरोपियन कमीशन ने आधिकारिक जानकारी दी कि भारत ईयू को टैरिफ में ऐसी छूट देगा, जो उसके किसी भी दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर को नहीं मिली है, जिससे ईयू एक्सपोर्ट के लिए भारतीय बाजार में पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। उदाहरण के लिए, कारों पर टैरिफ धीरे-धीरे 110 प्रतिशत से घटकर 10 फीसद हो जाएगा, जिसमें हर साल 250,000 गाड़ियों का कोटा होगा। मशीनरी पर 44 प्रतिशत, केमिकल्स पर 22 परसेंट और फार्मास्यूटिकल्स पर 11 प्रतिशत तक के ऊंचे टैरिफ को ज़ीरो पर ले आया जाएगा। टैरिफ एक टैक्स है, जो कोई देश अपने यहां विदेश से आयात होने वाले समान पर लगाता है। इससे विदेश से आने वाला सामान महंगा हो जाता है, और जिस देश में सामान आता है, उसे टैक्स से आय होता है।यूरोपियन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर एक चार्ट के ज़रिये सारा गणित समझाया है। कमीशन ने वर्ष 2024 को आकलन का आधार बनाया, जिसमें मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण पर 16.3 बिलियन यूरो बतौर टैरिफ देने पड़े थे। एफटीए के कार्यान्वयन के बाद, यूरोपीय संघ के देशों को टैरिफ की देनदारी ज़ीरो प्रतिशत हो जाएगी। विमान और अंतरिक्ष यान निर्यात पर 11 प्रतिशत के हिसाब से 6.4 अरब यूरो टैरिफ के रूप में 2024 में देना पड़ा था, आगे से यह शून्य हो जाएगा। ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण के एक्सपोर्ट पर 27.5 प्रतिशत के हिसाब से 3.4 बिलियन यूरो देना पड़ा था, इनमें से 90 फीसद प्रोडक्ट पर शून्य टैरिफ लगा करेगा। प्लास्टिक पर भी ज़ीरो टैरिफ लगा करेगा, जिससे यूरोपीय संघ के देशों को 2 अरब 20 करोड़ यूरो की बचत होगी।

दुनिया जल के वैश्विक दिवालियापन की ओर बढ़ रही है

जल संकट

निर्मल अग्निहोत्री

दरअसल, जल संकट अब 'वाटर स्ट्रेस' से आगे बढ़कर 'ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी' यानी दुनिया जल के वैश्विक दिवालियेपन की ओर बढ़ रही है। स्थिति यह है कि जल स्रोतों का दोहन इतनी तीव्रता से हो रहा है कि उनकी प्राकृतिक भरपाई असंभव होती जा रही है। भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है, नदियां सूख रही हैं और तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं।जल है तो जीवन है-यह पंक्ति कोई नारा भर नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का शाश्वत सत्य है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। किंतु विडंबना यह है कि जिस जल को हम जीवन का आधार मानते हैं, वही आज सबसे अधिक संकटग्रस्त संसाधन बन चुका है। देश-दुनिया में जल संकट के हालात विकराल हो चुके हैं और यह संकट अब केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही, भ्रष्टाचार और मूल्यहीन शासन का भी परिणाम बनता जा रहा है। विश्व स्तर पर लगभग 25 देश अत्यधिक जल तनाव से जूझ रहे हैं। चार अरब से अधिक लोग वर्ष में कम से कम एक माह पानी की गंभीर कमी का सामना करते हैं।

मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्र इस संकट की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहां 60 करोड़ से अधिक लोग उच्च जल तनाव वाले क्षेत्रों में रहते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्य सबसे अधिक प्रभावित हैं, जबकि चेन्नई, बेंगलूरु और दिल्ली जैसे महानगरों में पानी की कमी रोजमर्रा की समस्या बन चुकी है। दरअसल, जल संकट अब 'वाटर स्ट्रेस' से आगे बढ़कर 'ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी' यानी दुनिया जल के वैश्विक दिवालियेपन की ओर बढ़ रही है। स्थिति यह है कि जल स्रोतों का दोहन इतनी तीव्रता से हो रहा है कि उनकी प्राकृतिक भरपाई असंभव होती जा रही है। भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है, नदियां सूख रही हैं और तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं। यह संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संकट भी है। जल संकट का सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कृषि, उद्योग और ऊर्जा-तीनों ही क्षेत्र पानी पर निर्भर हैं। जब खेतों को पानी नहीं मिलता, उद्योग ठप होते हैं और बिजली उत्पादन प्रभावित होता है, तो देश की जीडीपी में 6 प्रतिशत तक की कमी का खतरा उत्पन्न हो जाता है। आमजन के लिए यह संकट जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन जाता है। जहां पानी पर्याप्त है, वहां बर्बादी हो रही है और जहां पानी की सबसे अधिक आवश्यकता है, वहां लोग बूंद-बूंद को तरस रहे हैं।भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय बनाया है। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रम इसी दिशा में ऐतिहासिक पहल हैं।

जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, ताकि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित किया जा सके। अटल भूजल योजना भूजल के सतत प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ÷हर खेत को पानी÷ के संकल्प को साकार करने का प्रयास है। इसके साथ ही जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और जनभागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। इन योजनाओं ने निश्चित रूप से जल संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत किया है। कई क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनी हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा मिला है और भूजल पुनर्भरण के प्रयास हुए हैं। लेकिन इस सकारात्मक तस्वीर के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है- प्रशासनिक भ्रष्टाचार। यही वह दीमक है जो इन योजनाओं की उपयोगिता और प्रासंगिकता को नष्ट कर रही है, उन्हें मूल्यहीन बना रही है।जल संकट से जुड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार कई रूपों में दिखाई देता है-घटिया निर्माण, फर्जी आंकड़े, अधूरी परियोजनाएं, कमीशनखोरी और जवाबदेही का अभाव। कहीं कागजों में ही वर्षा जल संचयन संरचनाएं बन जाती हैं, तो कहीं पाइपलाइन बिछाने में घटिया सामग्री का उपयोग होता है। कई स्थानों पर योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पाता। परिणाम यह होता है कि करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन न पानी मिलता है और न संकट कम होता है। भ्रष्टाचार केवल धन की बर्बादी नहीं करता, वह भविष्य की पीढ़ियों का अधिकार भी छीन लेता है।

इन जटिल होती जल संकट स्थितियों के प्रति नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों को बूंद-बूंद के लिये तरसना पडेगा। जल जैसे जीवनदायी संसाधन के साथ किया गया भ्रष्टाचार वास्तव में मानवता के साथ अपराध है। जब जल संरक्षण की योजनाएं कागजों में सिमट जाती हैं, तब जल संकट और भी गहरा हो जाता है। यही कारण है कि आज योजनाएं तो हैं, नीतियां भी हैं, लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, अतिदोहन, अनियंत्रित शहरीकरण और खराब प्रबंधन इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। परिणामस्वरूप वर्षा का पैटर्न बदल गया और जल स्रोत सूखते चले गए।

यूजीसी नियमों के विरोध में बिल्हौर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सोमवार को बिल्हौर तहसील परिसर में सवर्ण अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी डॉ. संजीव दीक्षित को सौंपा।

अधिवक्ताओं का कहना था कि प्रस्तावित नियमावली में कई प्रक्रियात्मक खामियां हैं। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगने की स्थिति में उसे अपनी बात रखने और निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर देने की स्पष्ट व्यवस्था ड्राफ्ट में नहीं है, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया गया।

ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से छात्र समुदाय और शिक्षा जगत से जुड़ी इन गंभीर चिंताओं पर विचार करने की मांग की गई। साथ ही यूजीसी से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया, ताकि कानून सभी वर्गों के लिए समान रूप से न्याय सुनिश्चित कर सके। अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि शिक्षा संस्थानों में लागू नियमावली चयनात्मक होगी, तो यह संविधान की मूल भावना के विपरीत होगी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का हवाला देते हुए कहा कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और भेदभाव से मुक्त न्याय मिलना चाहिए।

प्रदर्शन के दौरान अनिल अग्निहोत्री, शिवकांत तिवारी, अमित तिवारी, आदेश तिवारी, कुशल पांडेय, शीलू अग्निहोत्री, गौरव तिवारी, प्रवीण तिवारी और आशीष सिंह सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।

मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस की सूझबूझ से बची जान

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर क्षेत्र के अरौल थाना अंतर्गत सरैया दस्तम गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक गांव में स्थापित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को ऊंचाई पर खड़ा देख ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों द्वारा युवक को नीचे उतरने के लिए काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। हालात बिगड़ते देख ग्रामीणों ने तुरंत अरौल थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक अटल बिहारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने संयम और धैर्य के साथ युवक से संवाद स्थापित किया।

➪ नजारा देख पूरे गांव में अफरा-तफरी फैली

काफी देर समझाने के बाद पुलिस टीम ने युवक को सुरक्षित टावर से नीचे उतार लिया।

पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम संदीप उर्फ भूरा मुन्नू बताया। वह बिल्हौर थाना क्षेत्र के चौखंडी गांव का निवासी है और उसकी उम्र करीब 30 वर्ष बताई गई है। पुलिस द्वारा तत्काल उसके परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को सकुशल अपने साथ ले गए। घटना में किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने पुलिस की तत्परता, समझदारी और मानवीय रवैये की प्रशंसा की। समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और युवक की जान सुरक्षित बचा ली गई।

पुरानी रंजिश में ठेकेदार से मारपीट पिता-पुत्र समेत छह के खिलाफ केस

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

चौबेपुर/बिल्हौर (कानपुर)। थाना चौबेपुर क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे एक ठेकेदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पिता-पुत्र समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किदवई नगर थाना नौबस्ता निवासी ठेकेदार आयुष तिवारी के अनुसार, 25 जनवरी की शाम करीब 6 बजे वह अपने दो साथियों के साथ कस्बा चौबेपुर स्थित रामबाबू

➪ सड़क निर्माण ठेकेदार को घेरकर पीटा, क्षेत्र में काम न करने की धमकी

स्वीट हाउस पर जलपान कर बाहर निकले थे। इसी दौरान गड़ कुर्मीखेड़ा कला निवासी सूरज कटियार, रविकांत कटियार और उनके तीन-चार अज्ञात साथी मौके पर पहुंचे और उन्हें घेर लिया।

आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में ठेकेदार के बाएं हाथ के अंगूठे, सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।

जाते समय आरोपियों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत का हवाला देते हुए धमकी दी कि अब चौबेपुर क्षेत्र में ठेकेदारी नहीं करने दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर पिता-पुत्र समेत छह आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जा रही है।

मरियानी गांव में आकाशीय बिजली गिरी, बाल-बाल बचा पूरा परिवार

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

चौबेपुर/बिल्हौर(कानपुर) चौबेपुर क्षेत्र के मरियानी गांव में बुधवार सुबह मौसम ने अचानक कहर बरपा दिया। तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक ग्रामीण का मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त घर में सो रहा परिवार सुरक्षित बच गया, लेकिन घटना से गांव में दहशत फैल गई।

➪ तड़के गिरी बिजली से मकान हो गया क्षतिग्रस्त

मरियानी गांव निवासी राजू कश्यप अपने परिजनों के साथ मकान में सो रहे थे। सुबह करीब चार बजे तेज गर्जना के साथ बिजली सीधे उनके घर पर गिरी, जिससे जोरदार धमाका हुआ और पूरा मकान हिल गया। अचानक हुए हादसे से परिवार के लोग घबरा गए और अफरा-तफरी मच गई।

बिजली गिरने से मकान की छत और सीढ़ियों में कई जगह बड़े-बड़े छेद हो गए। छत का मलबा नीचे गिरने से घर के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा, वहीं दीवारों में भी गहरी दरारें आ गईं। परिवार के सदस्य किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे।

पीड़ित राजू कश्यप ने बताया कि आकाशीय बिजली की चपेट

में आने से घर में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर नष्ट हो गए। टीवी, फ्रिज, पंखे सहित पूरी वायरिंग खराब हो गई है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। परिवार सुरक्षित है, लेकिन क्षतिग्रस्त मकान को लेकर चिंता है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है।

जयतु जगदीश मण्डल सेवा समिति ने

77वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित किया विशाल अन्नदान सेवा कार्यक्रम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयतु जगदीश मण्डल सेवा समिति द्वारा अन्नदान सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत 'जयतु जगदीश प्रसादम सेवा' सार्वजनिक भण्डारे का भव्य आयोजन बिरहाना रोड स्थित कार्यक्रम स्थल पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ विधायक अमिताभ बाजपेई द्वारा भारत माता को माल्यार्पण एवं भोग अर्पित कर किया गया।

भण्डारे में दोपहर 12 बजे से देर शाम तक गर्मागर्म तहरी एवं मेवा युक्त हलवे का वितरण किया गया। आयोजन स्थल पर दोपहर से ही श्रद्धालुओं और नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। समिति के अनुसार लगभग 2000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में मण्डल की महिला शाखा की पदाधिकारियों एवं सदस्यों का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने सेवा कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाई।

इस अवसर पर वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डा0 श्याम बाबू गुप्ता, डा0 योगेश कुमार सक्सेना, क्षेत्रीय संयोजक विनोद गुप्ता, संरक्षक राजीव गुप्ता, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय गुप्ता, पार्षद विकास जयसवाल, पार्षद अमित गुप्ता, पार्षद आर्दश गुप्ता, पार्षद शिवम दीक्षित, जिला मंत्री भाजयुमो मीनाक्षी गुप्ता, अलंकार ओमर, निखिल गुप्ता सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मण्डल अध्यक्ष सत्य नारायण गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सागर गुप्ता एवं उपाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का बैच एवं पटका पहनाकर स्वागत किया। आयोजन में विष्णु गुप्ता, मयंक सक्सेना, अमित गुप्ता, हेमा ओमर, रीता गुप्ता, मीनाक्षी सक्सेना सहित अनेक कार्यकर्ता और सेवाभावी नागरिक मौजूद रहे।

एक शातिर को मुठभेड़ में पुलिस ने दबोचा, 2 साथी भी गिरफ्तार

26 जनवरी को घर के बाहर खड़ी महिला से लूटी थी चैन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। थाना अकबरपुर क्षेत्र में महिला से चैन झपटमारी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

26 जनवरी को यूपीएसआईडीसी जैनपुर क्षेत्र में महिला के घर के दरवाजे पर गले से जंजीर झपट ली गई थी। इस संबंध में थाना अकबरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने रात में चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों प्रदीप दीक्षित उर्फ दीपक दीक्षित व निखिल यादव को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से छीनी गई जंजीर के टुकड़े, अवैध तमंचा, कारतूस, दो मोबाइल फोन व पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई।

इसके बाद मुखबिर की सूचना पर आधू कमालपुर बंबा के पास पुलिस ने घेराबंदी की, जहां अभियुक्त धीरज गुर्जर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से अवैध असलहा, कारतूस, जंजीर का टुकड़ा व बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त का एक साथी नितिन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

फैक्ट्री मालिक रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप

कानपुर देहात। रनियां थाना क्षेत्र में एक महिला ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी एवं फैक्ट्री मालिक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रनियां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पीड़िता दूसरे जनपद की निवासी है और कानपुर देहात स्थित एक निजी तेल कंपनी में कार्यरत थी। महिला का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने उसे काम का झांसा देकर उसके गृह जनपद से कानपुर देहात बुलाया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने खुद को अविवाहित बताते हुए शादी का वादा किया और सेवानिवृत्ति के बाद फैक्ट्री में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। बाद में महिला को जानकारी मिली कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। पीड़िता ने बताया कि उसने पूर्व में भी रनियां थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी शिवनारायण सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज के युवा सड़क पर उतरे

काले बैनर और तिरंगे के साथ पैदल मार्च कर तहसील पहुंचे, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए यूजीसी कानून को लेकर सवर्ण समाज में रोष बढ़ता जा रहा है। विरोध के स्वर अब सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोगों द्वारा इस्तीफा दिए जाने की चर्चाओं के बीच अब खुले तौर पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं।

इसी क्रम में रसूलाबाद में सैकड़ों की संख्या में सवर्ण समाज के युवा काले बैनर और तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। युवाओं ने ÷काला कानून वापस लो÷ और ÷सरकार मुर्दाबाद÷ के नारे लगाते हुए लगभग एक किलोमीटर लंबा पैदल मार्च किया और रसूलाबाद तहसील पहुंचकर नायब तहसीलदार शिव दर्शन सिंह को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित था। इसमें यूजीसी से संबंधित नए कानून को छात्र विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस कानून पर पुनर्विचार नहीं किया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एडवोकेट बलराम सिंह चौहान, हर्षित बाजपेई, शिव ठाकुर, पंकज ठाकुर, आशुतोष पाठक सलोने, मयंक त्रिपाठी, गुल्ली बाजपेई, वैभव त्रिपाठी, राधेश्याम भदोरिया, अजय बाजपेई, सूरज त्रिपाठी, नवनीत शुक्ला, अविनाश मिश्रा, संजय बाजपेई, विपिन मिश्रा, सभासद अंकुर भदौरिया, दीपक, बउआ सिंह सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे।

भट्टा संचालकों की मनमानी से ग्रामीणों की जान खतरे में

रसूलाबाद में एक किलोमीटर सड़क बनी 'मौत का रास्ता', प्रशासन बेखबर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात।रसूलाबाद क्षेत्र में ईंट भट्टा संचालकों की लापरवाही और मनमानी अब ग्रामीणों की जान पर सीधा खतरा बनती जा रही है। सड़क पर फैलाई गई मिट्टी और हालिया बारिश के बाद बने कीचड़ ने आवागमन को पूरी तरह असुरक्षित कर दिया है। हालात इतने भयावह हैं कि लोग फिसलकर गिर रहे हैं और किसी बड़े हादसे की आशंका लगातार बनी हुई है।रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवनपुर से मिंडाकुआं के बीच करीब एक किलोमीटर लंबी सड़क पर आर.जे. ब्रिक फील्ड द्वारा मिट्टी फैलाए जाने से सड़क पूरी तरह फिसलन भरी हो गई है। इसी मार्ग से प्रतिदिन कई गांवों के ग्रामीण, स्कूली बच्चे और दोपहिया वाहन चालक गुजरते हैं, लेकिन अब यह सड़क सुरक्षित मार्ग नहीं बल्कि खतरे का जाल बन चुकी है।ग्रामीणों के अनुसार बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ फैल गया, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। खासकर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। रात के समय दृश्यता कम होने से दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी मार्ग पर पूर्व में मिट्टी से बनी फिसलन के कारण एक ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक छात्र की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बावजूद इसके न तो भट्टा संचालकों पर कोई प्रभावी कार्रवाई हुई और न ही प्रशासन ने कोई सबक लिया।नार खुर्द निवासी नदीम ने बताया कि बुधवार को कानपुर जाते समय उनकी बाइक फिसल गई, जिससे वे घायल हो गए। उन्होंने कहा कि अब महज एक किलोमीटर की सड़क पार करना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। पूर्व प्रधान अजय कुमार, पंकज सिंह सेंगर और शुभम दुबे का आरोप है कि क्षेत्र में भट्टा संचालकों ने पूरी तरह अराजकता फैला रखी है। खेतों से मिट्टी ढोने वाले तेज रफ्तार ट्रैक्टर बिना किसी नियंत्रण के सड़कों पर दौड़ रहे हैं,

जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक न तो सड़क से मिट्टी हटाई गई और न ही मरम्मत का कोई कार्य शुरू हुआ। प्रशासन की चुप्पी से लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

यूजीसी कानून के विरोध में मैथा तहसील में जोरदार प्रदर्शन

» हथकड़ियों और जंजीरों के साथ करणी सेना भारत व स्वर्ण समाज का धरना

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात।यूजीसी कानून के विरोध में सोमवार को कानपुर देहात जनपद की मैथा तहसील में करणी सेना भारत एवं स्वर्ण समाज के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में हथकड़ियाँ और जंजीरें पहनकर तहसील परिसर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी कानून को जनविरोधी बताते हुए इसे समाज के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया। तहसील परिसर में ÷यूजीसी काला कानून वापस लो÷, ÷एक हैं तो सेफ हैं÷, ÷अन्याय नहीं सहेंगे÷ जैसे नारों से माहौल गूंज उठा।आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि यूजीसी कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।इस आंदोलन का नेतृत्व करणी सेना भारत के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह गौर (कानपुर देहात) एवं मानव सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष त्रिवेदी ने किया। इस दौरान मानव सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने जंजीरों से बंधे हाथों के साथ प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी भेजा।वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी कानून समाज के हितों के खिलाफ है और इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन को जिला, मंडल और प्रदेश स्तर तक विस्तार दिया जाएगा।कार्यक्रम में एडवोकेट देवेंद्र तिवारी, राहुल दीक्षित, राजीव दीक्षित, धीरु अवस्थी, अंकित शुक्ला, अजय राजपूत, रामजी कुशवाहा, विवेक शुक्ला, अंकित द्विवेदी, सुमित पाठक सहित करणी सेना भारत व स्वर्ण समाज के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

यूजीसी के नए नियमों से अगड़े-पिछड़े में बढ़ी खाई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली/लखनऊ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू किए गए नए नियमों ने न सिर्फ विश्वविद्यालय परिसरों में, बल्कि समाज और राजनीति में भी हलचल मचा दी है। समानता और भेदभाव-निरोधक व्यवस्था के नाम पर लाए गए इन नियमों को लेकर हिन्दू समाज में अगड़े और पिछड़े वर्गों के बीच नई दरार उभर आई है, जिसका सीधा असर सियासत पर भी दिखाई देने लगा है।

यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले कथित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से नए नियम जारी किए, जो 15 जनवरी से देशभर के सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लागू कर दिए गए। इसके तहत हर संस्थान में समान अवसर केंद्र और समता समिति का गठन अनिवार्य किया गया है, जो भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करेगी।

हालांकि, इन नियमों को लेकर सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों में गहरी नाराज़गी देखी जा रही है। उनका आरोप है कि नियमों में भेदभाव की परिभाषा एकतरफा है, जिसमें केवल आरक्षित वर्गों को पीड़ित मानकर सामान्य वर्ग को संभावित दोषी के रूप में देखा गया है। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर कोई दंडात्मक प्रावधान न होने से दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है।

पूरे देश की सियासत गरमाई, आंदोलन तेज़

आलोचकों का कहना है कि भेदभाव रोकने के लिए पहले से ही संवैधानिक और संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद थीं, ऐसे में नए नियमों की आवश्यकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनका यह भी कहना है कि प्रारंभिक ड्राफ्ट में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन विरोध के बाद उन्हें जोड़ा गया, जिससे सामान्य वर्ग के छात्र पहले से अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। सवर्ण संगठनों का आरोप है कि भाजपा सरकार पिछड़े और दलित वर्गों को साधने के प्रयास में अपने पारंपरिक सवर्ण समर्थकों की अनदेखी कर रही है। कई संगठन इसे हिन्दू समाज को विभाजित करने की साजिश करार दे रहे हैं। सवर्ण आर्मी और राष्ट्रीय हिंदू सनातनी सेना जैसे संगठनों ने खुले तौर पर सरकार और यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

वहीं, समाजवादी पार्टी के लिए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से लाभकारी साबित होता दिख रहा है। पार्टी के नेता इसे सामाजिक न्याय से जोड़कर पिछड़े और दलित वर्गों को और मजबूती से अपने पक्ष में करने की रणनीति बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा को सवर्ण असंतोष से नुकसान की आशंका सताने लगी है।आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ के हजरतगंज में राष्ट्रीय हिंदू सनातनी सेना ने बड़ा प्रदर्शन किया और नियमों को ÷काला कानून÷ बताते हुए विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। जौनपुर, दिल्ली, जयपुर सहित कई शहरों में सवर्ण संगठनों ने ज्ञापन सौंपे और प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर नियमों की वापसी को लेकर अभियान तेज है।

इसी बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर आंदोलन का समर्थन कर सभी को चौंका दिया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के कई पदाधिकारियों के इस्तीफे ने पार्टी की चिंता और बढ़ा दी है।

हालांकि, आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से सामाजिक तनाव और राजनीतिक बयानबाज़ी बढ़ रही है, उससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस नियम के खिलाफ जनहित याचिका भी दाखिल हो चुकी है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया, तो यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है।

सवर्ण आर्मी ने भरी हुंकार
यूजीसी को नहीं करेंगे स्वीकार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। सवर्ण आर्मी के सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट पहुंचकर यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया बाद में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया। जिसमें कहा है कि सामान्य वर्ग के करोड़ो छात्रों एवं नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि असमानता का वातावरण उत्पन्न हो रहा है।सवर्ण आर्मी के संयोजक अमित प्रताप सिंह ने कहा कि जब तक इस अधिसूचना को वापस नहीं दिया जाता है सवर्ण आर्मी लोकतांत्रिक संवैधानिक एवं विधिक तरीकों से इसका विरोध करती रहेगी । उन्होंने कहा कि सवर्ण वर्ग देश के विकास प्रशासन शिक्षा उद्योग एवं राजस्व सृजन में समान वर्ग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यदि इस नियम को तत्काल वापस नहीं दिया गया तो इसका विरोध किया जाएगा।

यूजीसी के नए नियमों पर सीएम योगी का 'रुद्र' रूप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में यूजीसी रेगुलेशन्स 2026 को लेकर सियासी और प्रशासनिक भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इन्हें छात्रों, शिक्षकों और राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताया है। मुख्यमंत्री के तीखे तेवरों के बीच यह विवाद तब और गहरा गया जब पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने नियमों को भेदभावपूर्ण बताते हुए अपने पद से

इस्तीफा दे दिया।सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री का मानना है कि यूजीसी के नए नियम राज्यों के अधिकारों में सीधा हस्तक्षेप हैं और इससे न केवल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कमजोर होगी, बल्कि स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों और आरक्षण व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। योगी सरकार इसे संघीय ढांचे के खिलाफ मान रही है।पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे में कहा कि यूजीसी रेगुलेशन्स 2026 समान अवसर की भावना के विपरीत हैं और इससे वंचित वर्गों के साथ अन्याय होगा। उनका इस्तीफा प्रशासनिक गलियारों में बड़ी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह इस्तीफा आने वाले दिनों में अन्य अधिकारियों और शिक्षाविदों को भी खुलकर विरोध के लिए प्रेरित कर सकता है।

अपनी ही सरकार में यूजीसी के विरोध में कई विधायक

बीजेपी विधायक प्रतिक भूषण सिंह ने भी इन नियमों के खिलाफ खुलकर बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार छात्रों और शिक्षकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र से नियमों पर पुनर्विचार की मांग की और कहा कि उत्तर प्रदेश इस मुद्दे पर पीछे हटने वाला नहीं है।यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर खतराशिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नए यूजीसी नियमों से विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी लगभग समाप्त हो सकती है। नियुक्तियों, पाठ्यक्रम निर्धारण और प्रशासनिक फैसलों में केंद्रीय नियंत्रण बढ़ने से राज्य विश्वविद्यालय केवल आदेश पालन तक सीमित रह जाएंगे।आगे क्या? योगी सरकार अब इस मुद्दे पर अन्य राज्यों को साथ लाकर साझा रणनीति बनाने की तैयारी में है। संकेत हैं कि केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए राजनीतिक और संवैधानिक दोनों स्तरों पर कदम उठाए जा सकते हैं।सवाल बड़ा है–क्या केंद्र सरकार यूजीसी रेगुलेशन्स 2026 पर पीछे हटेगी, या यह टकराव और तेज होगा? आने वाले दिन देश की उच्च शिक्षा की दिशा तय कर सकते हैं।

मेले में दो पक्षों में हुआ विवाद ,फायरिंग में युवक के पैर में लगी गोली

» ग्रामीणों ने हमलावरों का पीछा मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को पकड़ा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

हमीरपुर। जनपद में राठ कोतवाली क्षेत्र के परा गांव में आयोजित मेले में बीते सोमवार रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और उसके बाद एक पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई। घटना में एक युवक को पृथ्वीराज गोली लग गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट के दौरान दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है।

राठ कोतवाली क्षेत्र के परा गांव में मेला के दौरान रामलीला मंचन की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान गांव के बाहर से आए करीब एक दर्जन लोगों का गांव के प्रधान जौहर सिंह राजपूत से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में पृथ्वीराज राजपूत की जांघ में गोली लगी। घायल को तुरंत राठ के सरकारी अस्पताल में भर्ती

कराया गया। ग्रामीणों ने हमलावरों का पीछा किया और मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों, प्रदीप खरेला और ब्रजकिशोर अनघोरा गांव निवासी को पकड़ लिया। प्रदीप और ब्रजकिशोर भी गंभीर रूप से घायल हो गए।राठ सीओ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि झगड़ा पुरानी रंजिश के चलते हुए था ,गोली लगने से घायल हुए पृथ्वीराज सिंह को झांसी रिफर कर दिया गया है अन्य घायलों का भी इलाज चल रहा है ,मामले के आरोपियों की तलाश की जा रही है।

दंगल में रोमांचक कुश्तियों ने दर्शकों का किया भरपूर मनोरंजन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

हमीरपुर। सुमेरपुर में स्वामी रोटीराम जी की पावन स्मृति में आयोजित यज्ञ की वर्षगांठ पर मुमुक्षु आश्रम में दो दिवसीय भव्य दंगल का आयोजन किया गया। मिट्टी के अखाड़े में जब पहलवानों ने दमखम दिखाया, तो दर्शकों की तालियों से पूरा आश्रम परिसर गूंज उठा।

दंगल का उद्घाटन यज्ञाचार्य बलदेव प्रसाद शास्त्री और स्वामी निर्भयचेतन ने संयुक्त रूप से किया, भाजपा नेता शिवशंकर सिंह खन्ना ने पहलवानों के हांथ मिलवाकर उनका उत्साह वर्धन किया, दंगल में बुधनी के राजू बाबा पहलवान ने कर्वी के संजय पहलवान को पटखनी दी, फिरोजाबाद के राहुल ने सोनीपत के मुमटी को शिकस्त दी, सैफई के पहलवान लोकेंद्र यादव ने कानपुर के चांद पहलवान को, इंगोहटा के कल्लू पहलवान ने लखनऊ के मुकेश को पटखनी दी। कल्लू ने एक अन्य मुकाबले में लकी (इंगोहटा) को भी शिकस्त दी। कानपुर के हर्ष तिवारी ने लखनऊ के विमलेश को हराकर जीत दर्ज की। हर्षवर्धन (इंगोहटा) ने आंशिक को और संतोष छानी ने दिलीप सढ़ा को हराकर कुश्ती जीती।

सफाई व्यवस्था पर प्रशासन की अनदेखी, बरसात में सातनपुर मंडी मार्ग बना कीचड़ का दलदल

जरा सी बारिश में फिसलन, भारी वाहनों को निकलना हुआ मुश्किल, दुर्घटनाओं का खतरा

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। सेंट्रल जेल चौराहे से सातनपुर मंडी को जोड़ने वाला मार्ग, जिसका निर्माण कुछ ही माह पूर्व कराया गया था, अब बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। मार्ग पर नियमित सफाई न होने के कारण जरा सी बारिश में सड़क पर कीचड़ फैल जाता है, जिससे मंडी समिति जाने वाले भारी वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी समय गंभीर मार्ग दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

मंगलवार रात और बुधवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद सातनपुर मंडी मार्ग पूरी तरह कीचड़युक्त हो गया। आलू लदे ट्रैक्टर और ट्रकों को मार्ग से निकालने में चालकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई स्थानों पर फिसलन के कारण वाहन फंसते नजर आए।

मंडी परिसर के आढ़तियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे कई बार मंडी सचिव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को मौखिक रूप से अवगत करा चुके हैं,

लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आढ़ती एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी अरविंद राजपूत ने बताया कि बरसात के मौसम में मंडी मार्ग की नियमित साफ-सफाई बेहद जरूरी है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे व्यापारियों के साथ-साथ आम राहगीरों को भी परेशानी

मार्ग की लाइटें टूटी, अंधेरे में बढ़ता खतरा

सातनपुर मंडी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जगह-जगह पानी और कीचड़ भरा हुआ है, वहीं कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। मंडी प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि रोशनी के लिए लगाई गई रोड लाइटें और हाई मास्ट लाइटें शो-पीस बनी हुई हैं। व्यापारियों का कहना है कि यह मार्ग शहर के भीतर जाने का प्रमुख रास्ता है, इसके बावजूद अनदेखी किए जाने से रोजाना लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

तटबंध बनाओ आंदोलनः 11 फरवरी से कढ़हर से अटैना तक पदयात्रा

हर गांव से पांच-पांच युवक होंगे शामिल, जनप्रतिनिधियों से सहयोग न मिलने का आरोप

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद।तटबंध निर्माण की मांग को लेकर तटबंध बनाओ जन संघर्ष समिति ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। समिति की बैठक ग्राम खुटिया में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 11 फरवरी से कढ़हर से अटैना घाट तक पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा में पूरे क्षेत्र से हजारों लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। बैठक में जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष भईयन मिश्रा ने कहा कि वर्षों से सरकार और जनप्रतिनिधियों से तटबंध बनवाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पूरा इलाका बाढ़ और कटान से प्रभावित है और तटबंध के बिना इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 11 फरवरी को पूरा क्षेत्र एकजुट होकर पदयात्रा में शामिल होगा और तटबंध निर्माण तक संघर्ष जारी रहेगा।

रमेश त्रिपाठी ने कहा कि यह समस्या किसी एक गांव की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की है।उन्होंने कहा कि हर गांव से कम से कम पांच-पांच युवक पदयात्रा में शामिल होंगे। प्रधान योगेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि तटबंध पूरे क्षेत्र के लिए जीवनरेखा साबित होगा और इसके लिए शासन को हर हाल में निर्णय लेना ही पड़ेगा।

11 फरवरी को सड़कों पर उतरेगा जनसैलाब

राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष कोमल पांडे ने कहा कि तटबंध के समर्थन में जनता पूरी तरह एकजुट है। 11 फरवरी को युवा जोश और अनुभवी लोगों की ताकत से यह पदयात्रा ऐतिहासिक रूप लेगी। बैठक में शिव शंकर मिश्रा, कमला शंकर तिवारी, ज्ञान स्वरूप पाठक, देवनारायण त्रिवेदी, बाबू अवस्थी, ओम नारायण त्रिवेदी, संजीव अग्निहोत्री, विपिन तिवारी, बृजेश मिश्र, बृजेश अग्निहोत्री, राम बिहारी वाजपेई, शरद अग्निहोत्री, अरुण मिश्रा, सोनू सिंह, जयवीर गौतम, राजाराम बाथम, रामानंद सक्सेना, राजीव वर्मा, अनूप प्रधान, भानु सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

फ्लाईओवर के नीचे ‘दैनिक टैक्स’ का आतंक

- मेडिकल कॉलेज के सामने गरीब दुकानदारों से 300 रुपये रोज़ की वसूली?
- नगर निगम ठेके पर वसूली का आरोप, डीएम के हस्तक्षेप से मचा हड़कंप

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।अयोध्या-आजमगढ़ मार्ग पर स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज, दर्शननगर के सामने फ्लाईओवर के नीचे रोज़ी-रोटी कमा रहे छोटे दुकानदारों की जिंदगी पर कथित अवैध वसूली का साया मंडराने लगा है। फल, चाय, समोसा, जूस और भोजन बेचकर मरीजों व तीमारदारों की जरूरतें पूरी करने वाले दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम के ठेकेदार के सहयोगी उनसे प्रतिदिन 300 रुपये की जबरन वसूली कर रहे हैं।

दुकानदारों का दर्द साफ है कि सुबह से रात तक 12 से 14 घंटे खड़े रहकर मुश्किल से 500 से 600 रुपये की कमाई होती है। ऐसे में रोज़ 300 रुपये ÷ठेके÷ के नाम पर देना सीधे पेट पर लात है। कई दुकानदारों ने शुरू में डर के कारण पैसे दिए, लेकिन जब वसूली का दबाव बढ़ा, तो विरोध फूट पड़ा।

ठेके के नाम पर फरमान?

बताया जा रहा है कि हाल ही में अयोध्या नगर निगम ने शहर के कई फ्लाईओवर के नीचे ठेले-खोमचे लगाने वालों से दैनिक वसूली का ठेका जितेंद्र यादव निवासी कुशमाहा को दिया है। आरोप है कि इसी ठेके की आड़ में मेडिकल कॉलेज के सामने बैठे दुकानदारों को प्रति ठेला/रेहड़ी/दुकान 300 रुपये प्रतिदिन देने का फरमान सुनाया गया। जब बात नहीं बनी, तो दुकानदारों ने सीधे जिलाधिकारी अयोध्या के सीयूजी नंबर पर शिकायत की। शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जबरदस्ती वसूली पर तत्काल रोक लगाई। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

ठेकेदार का बयान

सहमति से ही वसूली

ठेकेदार जितेंद्र कुमार यादव का कहना है कि इस विषय पर व्यापारियों से सहमति के लिए बातचीत चल रही है और उनकी रजामंदी के बिना कोई वसूली नहीं होगी। मामले पर अपर आयुक्त नगर निगम, अयोध्या नागेंद्र प्रसाद ने दो टूक कहा कि निगम और ठेकेदार के बीच हुई संविदा में शर्तें साफ़-साफ़ लिखी हैं। उन्होंने चेतावनी दी शर्तों का उल्लंघन हुआ तो ठेकेदार की सिक्योरिटी जब्त कर करार समाप्त कर दिया जाएगा।

होटल निर्माण में बाधा, खौफ दिखा कर वसूली

» अयोध्या में होटल बनाना बना गुनाह,मांगी जा रही रंगदारी

» ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर हुआ था विवाद : सीओ सदर

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में अब विकास के साथ-साथ दबंगई भी तेजी से निर्माणाधीन है। रौनाही थाना क्षेत्र के मुबारकगंज हाइवे पर बन रहे एक होटल को लेकर सामने आया मामला सिर्फ रंगदारी का नहीं, बल्कि कानून को खुली चुनौती देने का है। यहां होटल निर्माण के नाम पर पैसे की मांग, मारपीट, जातिसूचक अपशब्द और जान से मारने की धमकी का सनसनीखेज आरोप सामने आया है, जिसका वीडियो भी अब चर्चा में है। स्वराज इंडिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

पीड़ित होटल मालिक राकेश वर्मा के मुताबिक, कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग लंबे समय से होटल निर्माण को लेकर दबाव बना रहे थे। कभी ÷काम रुकवा देंगे÷ की धमकी, तो कभी ÷अंजाम बुरा होगा÷ का डर। आरोप है कि ये लोग खुद को प्रभावशाली बताते हुए चुनावी खर्च के नाम पर जबरन मोटी रकम की मांग कर रहे थे। 27 जनवरी की सुबह करीब 10ः40 बजे, एक कार से कुछ लोग होटल परिसर पहुंचे। आते ही मजदूरों के साथ गाली-गलौच शुरू हुई और निर्माण कार्य जबरन बंद करा दिया गया। जब होटल मालिक ने विरोध किया, तो बात बहस से निकलकर हिंसा में बदल गई। आरोप है कि दबंगों ने होटल मालिक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। दाहिने हाथ की उंगली फट गई, सिर में गंभीर चोट आई और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। बीच-बचाव करने आए एक बुजुर्ग सहित अन्य लोगों के साथ भी अभद्रता की गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, दबंगों ने होटल परिसर में दोबारा घुसकर मारपीट की और साफ शब्दों में कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो निर्माण हमेशा के लिए रुकवा दिया जाएगा। घटना के बाद से पीड़ित और उसका परिवार भय और मानसिक तनाव में है। होटल मालिक का कहना है कि वह कानून पर भरोसा करता है, लेकिन दबंगों के हौसले देखकर जान-माल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है।मामले में प्रभारी निरीक्षक लालचंद सरोज से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। वहीं, पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि होटल के पास ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर विवाद था। उन्होंने बताया कि तहरीर मांगी गई है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह भी दावा है कि जातिसूचक शब्दों के प्रयोग की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, पीड़ित होटल मालिक राकेश वर्मा की ओर से थाना रौनाही में नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी गई है।

इस्तीफे का ड्रामा, विकलांगता का फर्जीवाड़ा!

» डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह पर सगे भाई के सनसनीखेज आरोप

» भाई ने खोली पोल, इस्तीफा नहीं, जांच से भागने की एक चाल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

जांच अंतिम चरण में, उसी वक्त 'आंसुओं वाला इस्तीफा'

सूत्रों के अनुसार, शिकायत के बाद शुरू हुई विभागीय और मेडिकल जांच अब फाइनल स्टेज में है। ठीक उसी समय, आज प्रशांत सिंह ने रोते हुए इस्तीफा देकर खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश की और बहस को सीएम योगी के अपमान की भावनात्मक दिशा में मोड़ दिया। डॉ. विश्वजीत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इस्तीफे के नाटक से भ्रमित न हुआ जाए, पूरी जांच को उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाए। ऐसे में अगर आरोप सही हैं, तो जिम्मेदार अफसरों पर कब होगी कार्रवाई? अयोध्या से उठा यह मामला अब एक अफसर के इस्तीफे से आगे बढ़कर सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर रहा है। अब निगाहें मुख्यमंत्री कार्यालय और जांच एजेंसियों पर हैं क्या सच सामने आएगा या फिर आंसुओं की आड़ में फाइलें दफन हो जाएंगी?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथित अपमान की बात कहकर स्टेट जीएसटी विभाग से इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के मामले में अब ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने पूरे प्रकरण की दिशा ही बदल दी है। यह खुलासा किसी विरोधी ने नहीं, बल्कि उनके सगे बड़े भाई डॉ. विश्वजीत सिंह ने किया है और आरोप सीधे नौकरी में फर्जीवाड़े, झूठी विकलांगता और जांच से बचने की साजिश तक जा पहुंचते हैं।

स्वराज इंडिया FOLLOW UP

डॉ. विश्वजीत सिंह का आरोप है कि प्रशांत सिंह का यह इस्तीफा किसी आत्मसम्मान का नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति है ताकि चल रही जांच और संभावित रिकवरी से बचा जा सके।

उनके मुताबिक, प्रशांत सिंह ने नेत्र विकलांगता का फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की।

भाई का दावा है कि प्रशांत सिंह ने खुद को 40 प्रतिशत नेत्रहीन दर्शाया, जबकि जिस आंख की बीमारी का हवाला दिया गया है, वह 50 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति में दुनिया भर में नहीं पाई जाती। यही नहीं, आरोप है कि जांच के दौरान प्रशांत सिंह दो बार मेडिकल बोर्ड के सामने पेश ही नहीं हुए, जिससे संदेह और गहराता है।

मामला यहीं नहीं रुकता। डॉ. विश्वजीत सिंह ने डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर का भी गंभीर आरोप लगाया है।

उनका कहना है कि उम्र और विकलांगता–दोनों बिंदुओं पर कागजी खेल कर सरकारी सेवा में प्रवेश पाया गया।

संत ने प्रधानमंत्री से लगाई इच्छामृत्यु की गुहार

» यूजीसी कानून के विरोध में अयोध्या के संत परमहंस दास का प्रधानमंत्री को पत्र

» यूजीसी कानून वापस हो या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए : परमहंस दास

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या जहां संत परंपरा ने सदियों तक सत्ता को आईना दिखाया आज फिर एक संत की पीड़ा से कांप उठी है। इस बार न कोई आंदोलन है, न जुलूस बल्कि एक पत्र है, जो सीधे देश के प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया है। पत्र लिखने वाले हैं स्वामी परमहंस दास, और शब्द इतने तीखे हैं कि व्यवस्था की चुप्पी को भी कठघरे में खड़ा कर देते हैं। स्वामी परमहंस दास ने प्रधानमंत्री से दो टूक कहा है या तो यूजीसी कानून वापस लिया जाए, या मुझे इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए।÷ यह कोई भावनात्मक अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि उस हताशा का दस्तावेज़ है, जहां एक संत को लगता है कि उसकी आवाज़ सुनने वाला अब कोई नहीं बचा।

यूजीसी कानून को लेकर उठी आपत्तियों के बीच संत परमहंस दास का यह पत्र सवाल बनकर खड़ा है। उनका कहना है कि यह कानून शिक्षा, सनातन परंपरा और स्वतंत्र चिंतन पर कुठाराघात है। एक ऐसा संत, जिसने जीवन भर त्याग और तपस्या को चुना, आज कह रहा है कि अगर बात नहीं सुनी जाती तो मृत्यु ही अंतिम विकल्प है। यह केवल कानून का विरोध नहीं, यह उस व्यवस्था के प्रति अविश्वास है जो संवाद की जगह मौन चुनती जा रही है।

अयोध्या की धरती गवाह रही है कि यहां के संत सत्ता के अनुगामी नहीं, बल्कि उसके नैतिक नियंत्रक रहे हैं।

स्वामी परमहंस दास का पत्र उसी परंपरा की अगली कड़ी है जहां संत सवाल पूछता है, कीमत चुकाने को तैयार रहता है, लेकिन चुप नहीं रहता।

उनकी गुहार यह भी बताती है कि आज का संत खुद को इतना अकेला महसूस कर रहा है कि उसे प्रधानमंत्री से मृत्यु की अनुमति मांगनी पड़ रही है। लोकतंत्र के लिए खतरनाक चुप्पी।

हफ्ते में दो दिन छुट्टी के लिए हड़ताल, 100 करोड़ का लेनदेन प्रभावित

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर मंगलवार को जिले में बैंक कर्मियों ने कामकाज ठप रखा। हड़ताल के कारण अयोध्या में लगभग 100 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की अयोध्या इकाई के बैनर तले विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने-अपने बैंकों में ताले बंद रखे और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा सिविल लाइन के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की।प्रदर्शन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यूएफबीयू के संयोजक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले सात-आठ वर्षों से बैंक कर्मचारी पांच दिवसीय कार्य प्रणाली लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सात दिसंबर 2023 को इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच पांच दिवसीय कार्य प्रणाली को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक भारत सरकार की ओर से इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसी उपेक्षा के विरोध में हड़ताल की गई।सेंट्रल बैंक यूनियन के प्रांतीय महामंत्री केके रस्तोगी ने कहा कि बीते दो महीनों से बैंक कर्मचारी धरना, प्रदर्शन और अन्य लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज को अनसुना कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विभिन्न बैंकों के यूनियन बैंक के एकांत सिन्हा, बैंक ऑफ बड़ौदा के अमित यादव, पंजाब नेशनल बैंक के अशोक पांडे, यूको बैंक के मनोज सिंह, केनरा बैंक के निशांत सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी और अन्य वित्तीय संस्थानों में पांच दिवसीय कार्य प्रणाली लागू है।

हाउस अरेस्ट का आरोप, पुलिस के कड़े पहरे में अलंकार अग्निहोत्री

एडीएम कंपाउंड पुलिस छावनी में बदला, सीसीटीवी और पीएसी की तैनाती

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बरेली। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ब्राह्मण बटुकों पर कथित अत्याचार और यूजीसी के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा देने वाले निलंबित पीसीएस अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने खुद को 'हाउस अरेस्ट' में बताया है। उनका कहना है कि एडीएम कंपाउंड को मिनी जेल में तब्दील कर दिया गया है और उन्हें बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही।

अलंकार अग्निहोत्री के मुताबिक, उनका मौलिक अधिकार है कि वे कहीं भी आ-जा सकें, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो बाहर जाने दिया जा रहा है और न ही खाने-पीने के लिए निकलने की इजाजत है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह भंग हो चुकी है और प्रशासनिक दबाव के जरिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर, प्रशासन ने मंगलवार देर रात एडीएम कंपाउंड की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी। मुख्य गेट पर आवाजाही सीमित कर दी गई है और वहां पुलिस व पीएसी की तैनाती की गई है। परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। एक गेट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरे गेट से केवल पहचान और पूछताछ के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है।बीते दो दिनों से अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में जुट रहे लोगों को अब परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही।

प्रशासन उन लोगों की भी जानकारी जुटा रहा है, जो हाल के दिनों में सिटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहे हैं। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं किसी प्रभाव या बहकावे में आकर उन्होंने यह कदम तो नहीं उठाया।

मंगलवार शाम 7:48 बजे अलंकार अग्निहोत्री ने व्हाट्सएप स्टेटस जारी कर लिखा कि वह एडीएम कंपाउंड में हाउस अरेस्ट हैं और फिलहाल केवल फोन के जरिए ही संवाद संभव है। उन्होंने यह भी अपील की कि यदि वह संपर्क से बाहर हो जाएं तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट दाखिल की जाए।एक अन्य स्टेटस में उन्होंने दावा किया कि कंपाउंड में जैमर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काटा जा सके। वहीं, शासन स्तर पर पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है और अधिकारियों को मामले का शीघ्र समाधान निकालने के निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ भीगा, सर्दी और तीखी पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- रातभर बारिश, तेज हवाओं से बढ़ी गलन, कई इलाकों में जलभराव
- आईएमडी की चेतावनी पूरे हफ्ते यूपी में बारिश और तापमान में गिरावट के आसार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार देर रात शुरू हुई बारिश का सिलसिला बुधवार सुबह तक जारी रहा। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से गलन भरी ठंड में इजाफा हो गया है। रातभर हुई बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को सुबह आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस सप्ताह उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है और तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी।

बुधवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और रुक-रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में हल्का कोहरा छा सकता है। न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तेज हवाएं लगभग 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे ठंड और अधिक महसूस की जा रही है। आने वाले दिनों में बादल, नमी और ठंडी हवाओं के कारण मौसम और सर्द होने के आसार हैं।

यूजीसी के समता विनियम 2026 पर अभाविप ने जताई आपत्ति, स्पष्टता और संतुलन की उठाई मांग

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी ÷उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम, 2026÷ के उद्देश्य को सराहनीय बताया है, लेकिन इसके प्रावधानों में स्पष्टता और संतुलन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। अभाविप का कहना है कि विनियमों की अस्पष्ट शब्दावली के कारण समाज, विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

अभाविप ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए और शिक्षा परिसरों में किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संगठन ने यूजीसी से मांग की है कि वह उत्पन्न हो रही भ्रांतियों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी करे, ताकि किसी भी प्रकार की विभाजनकारी स्थिति से बचा जा सके।

अभाविप ने यह भी उल्लेख किया कि यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में यूजीसी को अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए शीघ्र हलफनामा दाखिल करना चाहिए, जिससे स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सके।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि शैक्षणिक परिसरों में सौहार्द और समानता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक समानता और भेदभाव-मुक्त वातावरण लोकतांत्रिक मूल्यों की बुनियाद है। विनियम को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए यूजीसी को सभी हितधारकों से संवाद स्थापित कर तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए।

वहीं, अभाविप कानपुर प्रान्त के प्रान्त मंत्री दिनेश यादव ने कहा कि विनियमों का उद्देश्य सकारात्मक है, लेकिन उनकी अस्पष्टता के कारण भ्रम की स्थिति बन रही है। उन्होंने यूजीसी से शीघ्र कदम उठाकर समता, सौहार्द और भेदभाव-मुक्त शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की।

अभाविप ने स्पष्ट किया कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा परिसरों में सकारात्मक, समतायुक्त और लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण सभी के सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

अयोध्या सीट पर पहला हक विनय कटियार का: बृजभूषण शरण सिंह

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- पूर्व सांसद बोले सीट पार्टी तय करेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ना पक्का
- यूजीसी नियमों से लेकर पार्टी संगठन तक, कई मुद्दों पर खुलकर रखी बात

अयोध्या। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अयोध्या लोकसभा सीट पर पहला अधिकार विनय कटियार का है और उन्हें ही चुनाव लड़ना चाहिए। एक मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह 2029 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, हालांकि किस सीट से, इसका फैसला पार्टी करेगी।बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 2023-24 में उनके खिलाफ साजिश हुई थी, इसी कारण उन्होंने लोकसभा जाने की बात कही थी।

पूर्व सांसद ने दोहराया कि उन्हें किसी भी हाल में एक बार संसद पहुंचना है। साथ ही उन्होंने विधायकों-सांसदों की बैठकों का समर्थन किया और कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पूर्व सांसद ने यूजीसी के नए नियमों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरी जानकारी मिलने के बाद ही इस पर बोलना उचित होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अपने संबंधों को बेहतर बताया और कहा कि उनकी विचारधारा पूरी तरह भाजपा के साथ है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com